मध्य पूर्व तनाव के बीच आरबीआई सतर्क

तेल और व्यापार पर निर्भरता से बढ़ी चिंता

डेटा आधारित नीति, जल्दबाजी से इनकार

नई दिल्ली, 21 अप्रैल. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच साफ संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल 'वेट एंड वॉच' मोड में है.

खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के जोखिम पैदा कर सकती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्याज दरों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और आगे के फैसले पूरी तरह से आंकड़ों और परिस्थितियों के आकलन पर आधारित होंगे.

गवर्नर मल्होत्रा ने यह भी कहा कि वास्तविक चिंता केवल तत्काल प्रभावों की नहीं है, बल्कि 'दूसरे दौर के प्रभावों' की है. इसका मतलब है कि अगर शुरुआती झटकों के बाद भी कीमतों और आपूर्ति में अस्थिरता बनी रहती है, तो यह धीरे-धीरे पूरे आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर सकती है. इससे मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है, जो दीर्घकालिक महंगाई का कारण बन सकता है.

मल्होत्रा ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत के लिए आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. भारत के कुल निर्यात का लगभग छठा हिस्सा और आयात का पांचवां हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा कच्चे तेल के आयात का करीब आधा हिस्सा और उर्वरकों का एक बड़ा भाग भी इसी क्षेत्र से आता है. यही नहीं, भारत को मिलने वाली कुल रेमिटेंस का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भी इसी क्षेत्र से आता है. ऐसे में वहां किसी भी प्रकार का भू-राजनीतिक तनाव भारत की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है.

उन्होंने विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं को लेकर चेतावनी दी. उनका कहना था कि यदि यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है और आपूर्ति में व्यवधान जारी रहता है, तो इसका असर केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि व्यापक स्तर पर महंगाई को बढ़ावा दे सकता है. खासकर ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन, उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

एलपीजी डिलीवरी सामान्य ऑनलाइन बुकिंग बढ़ी

नई दिल्ली, 21 अप्रैल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया है कि वर्तमान में पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और किसी भी प्रकार की आपूर्ति संबंधी बाधा नहीं है.

मंत्रालय के अनुसार डिजिटल माध्यमों से एलपीजी बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यह अब लगभग 98 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है.सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक स्तर पर कुछ भू-राजनीतिक परिस्थितियों और ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में घरेलू ईंधन आपूर्ति स्थिर और नियंत्रित है. वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर केंद्रों के संचालन समय में विस्तार किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है. मार्च 2026 से अब तक 1.28 लाख से अधिक छापेमारी अभियान चलाए गए हैं, जिनमें लगभग 59 हजार अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं. सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है.

भारत-दक्षिण कोरिया वित्तीय सहयोग को नई रफ्तार

सीतारमण-एफएससी प्रमुख बैठक, फिनटेक व निवेश पर जोर

डिजिटल पेमेंट्स और लोकल करेंसी सेटलमेंट पर चर्चा

नई दिल्ली, 21 अप्रैल. भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के चेयरमैन ली इओग-वेओन से मुलाकात की.

इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के साथ-साथ नई संभावनाओं को तलाशने पर व्यापक चर्चा हुई. वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस बैठक में केवल औपचारिक बातचीत ही नहीं हुई, बल्कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग की दिशा में विचार-विमर्श किया गया. बैठक में फिनटेक इनोवेशन, डिजिटल पेमेंट्स, निवेश के अवसर, लोकल करेंसी सेटलमेंट और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट आईएफएससी) में व्यापारिक संभावनाओं जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. यह संकेत देता है कि दोनों देश पारंपरिक आर्थिक संबंधों से आगे बढ़कर आधुनिक और तकनीक-आधारित वित्तीय साझेदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं. इस बैठक में एफएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे, जिनमें डायरेक्टर जनरल यूएन योसेओप और इंटरनेशनल फाइनेंस डिवीजन की डायरेक्टर किम यूनही प्रमुख रूप से उपस्थित थे. उनकी मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि दक्षिण कोरिया भी भारत के साथ वित्तीय सहयोग को रणनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर है.

> दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सहयोग को मजबूत करना बेहद आवश्यक है. खासकर फिनटेक और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में भारत की तेजी से बढ़ती क्षमता और दक्षिण कोरिया की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर एक मजबूत साझेदारी का आधार बना सकती है. भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हो रही प्रगति को देखते हुए कोरिया के लिए यहां निवेश और साझेदारी के बड़े अवसर मौजूद हैं.

सोना सस्ता, चांदी में बड़ी गिरावट

नई दिल्ली, 21 अप्रैल. आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्की से मध्यम गिरावट देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोना भी मामूली रूप से सस्ता हुआ. बाजार में यह उतार-चढ़ाव वैश्विक संकेतों और घरेलू मांग में बदलाव के चलते देखा जा रहा है.

एमसीएक्स पर 5 मई डिलीवरी वाली चांदी करीब 2300 रुपये से ज्यादा टूटकर लगभग 2,50,210 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई. वहीं, 5 जून डिलीवरी वाली चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 150 रुपये की कमजोरी के साथ कारोबार कर रही थी.सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोना लगभग 10 रुपये की हल्की गिरावट के साथ 1,55,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा. इसी तरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई.

सर्राफा बाजार के अनुसार, प्रमुख शहरों में भी सोने के दाम लगभग स्थिर से कमजोर रहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग समान स्तर पर कारोबार कर रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल और डॉलर की मजबूती- कमजोरी के आधार पर सोने-चांदी के दामों में और बदलाव देखने को मिल सकता है.

वीआईटी-टाटा मोटर्स में शिक्षा समझौता

नई दिल्ली 21 अप्रैल, वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (वीआईटी) ने टाटा मोटर्स यात्री वाहन लिमिटेड (टीएमपीवी) के साथ आधिकारिक रूप से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक सहयोग निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर वीआईटी की रजिस्ट्रार डॉ. टी. जयभारती और टाटा मोटर्स यात्री वाहन लिमिटेड के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री सीताराम कांडी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसका आदान-प्रदान 16 अप्रैल 2026 को पुणे स्थित परिसर में किया गया।

इस समझौते के अंतर्गत, वीआईटी आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से टाटा मोटर्स के

रानीपेट संयंत्र के टीएमपीवी कर्मचारियों के लिए बी.टेक (निर्माण अभियांत्रिकी) कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।

एमओयू का औपचारिक आदान-प्रदान वीआईटी के माननीय कुलाधिपति डॉ. जी. विश्वनाथन और टाटा मोटर्स के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी श्री सीताराम कांडी द्वारा किया गया।

टाटा मोटर्स की ओर से उपाध्यक्ष (संचालन) श्री प्रमोद चौधरी, वरिष्ठ महाप्रबंधक (यात्री वाहन संचालन) श्री नीरज अग्रवाल, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री विवेक बिंद्रा, महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं विकास) डॉ. रंगा गुंती, महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं विकास) श्री मार्सेल फर्नांडीस, महाप्रबंधक एवं प्रमुख (प्रारंभिक करियर एवं परिसर कार्यक्रम) श्री राजीव रंजन, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री अभ्युदय द्विवेदी तथा अन्य टीम सदस्य उपस्थित रहे।

वीआईटी की ओर से उपाध्यक्ष डॉ. शंकर विश्वनाथन एवं डॉ. सेकर विश्वनाथन, कुलपति डॉ. कंचना भास्करन, निदेशक (निरंतर व्यावसायिक विकास केंद्र) डॉ. सैमुअल राजकुमार, अधिष्ठाता (यांत्रिक अभियांत्रिकी संकाय) डॉ. कुप्पन पी., सहायक निदेशक (करियर विकास केंद्र) डॉ. गौरव सुशांत तथा क्षेत्रीय प्लेसमेंट अधिकारी श्री साबदे अमित सुरेश, पुणे उपस्थित रहे।

रिलायंस डिस्काउंट में मिलेंगे जबरदस्त ऑफर्स

नई दिल्ली, 21 अप्रैल. रिलायंस डिजिटल, यह इंडिया का सबसे बड़ा कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, जिसने अपने लंबे समय से इंतजार की जा रही 'डिजिटल डिस्काउंट डेज़' कैम्पेन के फिर से आने की घोषणा की है. इससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान ही नहीं बल्कि फायदेमंद भी हो जाएगा.

इस कैम्पेन के अंतर्गत, ग्राहक लीडिंग बैंक के कार्ड्स पर 26,000 तक इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं या पेपर फाइनान्स पर 30,000 तक कैशबैक का विकल्प चुन सकते हैं. इसके अलावा, रिलायंस डिजिटल सेकंड प्रोडक्ट पर दे रहा है फ्लैट 50% की छूट, जिससे ऑडियो डिवाइस, वेयरेबल्स, मोबाइल और लैपटॉप एक्सेसरीज़, चुनिंदा होम एंटरटेनमेंट और छोटे अप्लायंसेज़ जैसी कैटेगरी में कई चीज़ें खरीदने को बढ़ावा मिलेगा.

इसमें हिस्सा लेने वाले ब्रांड्स में मार्शल, जेबीएल, बोट और वनप्लस शामिल हैं, जो लोकप्रिय कंज़्यूमर टेक इकोसिस्टम पर कंपनी के मजबूत फोकस को दर्शाता है.

> रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीज़ें जैसे वायरलेस माउस, लैपटॉप एक्सेसरीज़, पावर बैंक और सैंडविच मेकर जैसे छोटे किचन अप्लायंसेज़ भी इस स्कीम का हिस्सा हैं, जो आपको 300 से 750 की रेंज में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे.

होर्मुज तनाव से तेल कीमतें उछलीं

नई दिल्ली, 20 अप्रैल अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बढ़े तनाव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर देखने को मिल रहा है.

ताजा घटनाक्रम के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच गई है और निवेशकों की चिंता बढ़ गई है. रिपोर्टों के अनुसार, होर्मुज क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव, जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध और दोनों देशों के बीच नाकेबंदी जैसी स्थितियों ने तेल आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ा दी हैं. इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति गुजरती है, ऐसे में किसी भी तरह की बाधा सीधे वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित करती है.

तनाव बढ़ने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 5 से 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह उछाल बाजार में बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और संभावित आपूर्ति संकट का संकेत है.

भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी

753 अंक से चढ़ा सेंसेक्स

211 अंक ऊपर रहा निफ्टी

मुंबई, 21 मार्च अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप मिलने की उम्मीद में मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स 753.03 अंक (0.96 प्रतिशत) चढ़कर 79,273.33 अंक पर पहुंच गया.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 211.75 अंक यानी 0.87 प्रतिशत ऊपर 24,576.60 अंक पर बंद हुआ. यह दोनों सूचकांकों का 05 मार्च के बाद का उच्चतम स्तर है.

अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आगे की वार्ता के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया है. निवेशकों को उम्मीद है कि इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के लिए नये अवसर खुलेंगे और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा.

बाजार में लिवाली चौतरफा रही और निवेशकों ने मझौली तथा छोटी कंपनियों में भी विश्वास दिखाया. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.47 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.88 प्रतिशत चढ़ा. फार्मा और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों की हल्की गिरावट को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक ऊपर रहे.

समाचार विशेष

तालमेल के लिए एक नेता की जरुरत

वेणुगोपाल इस जरुरत को पूरा नहीं कर पा रहे

केरल. कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता की जरुरत है, जो पार्टी के अंदर सभी नेताओं और प्रादेशिक क्षत्रपों के बीच समन्वय बना कर चले और साथ ही पार्टी के बाहर सहयोगी दलों के साथ भी तालमेल संभाले. अहमद पटेल के बाद से ही कांग्रेस को ऐसे नेता की जरुरत थी. राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव बना कर पिछले कई साल से रखा हुआ है लेकिन वे इस जरुरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.

यहां तक कि अपने राज्य केरल में भी वे तालमेल नहीं बना सके. केरल में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीत जाए लेकिन उससे पहले तमाम ओपिनियन पोल जो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं उसका कारण यह है कि पार्टी में बिखराव बहुत है. अंदरखाने घमासान छिड़ा है. सोचें, केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं और

वहां भी वे तालमेल नहीं बनवा पाए.

केरल में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की है. एक तरफ सीपीएम की ओर से बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी जीत होगी तो पिनरायी विजयन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे. दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पांच लोगों की दावेदारी बताई जा रही है, जिनमें एक नाम खुद केसी वेणुगोपाल का है. सोचें, वे संगठन महासचिव हैं और केरल में सीएम पद के दावेदार भी हैं. हैरानी की बात यह है कि पार्टी या खुद वेणुगोपाल की ओर से इसका खंडन नहीं किया जा रहा है. यह बात फैलने दी गई कि वे सीएम बन सकते हैं.

> मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस तरह का कोई व्यक्ति राजनीतिक सचिव के तौर पर होना चाहिए, जो अखिल भारतीय राजनीति समझता हो और देश भर के कांग्रेस नेताओं से उसका संपर्क या उसकी जान पहचान हो. पहले कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होता था. लेकिन अब राहुल गांधी का सबसे मजबूत पावर सेंटर है. इसलिए राहुल गांधी के पास भी एक राजनीतिक सचिव होना चाहिए, जो तालमेल का काम संभाले. इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन महासचिव के रूप में काम करने के लिए ऐसे व्यक्ति की जरुरत है, जो देश की राजनीति को समझता हो. राजनीतिक समझ के साथ साथ भाषा के स्तर पर भी नेताओं के साथ संवाद करने में सक्षम हो और सहज उपलब्ध हो.

विजय को ईसाई होने का मिल रहा गजब फायदा

चेन्नई. फिल्मों से राजनीति में आने वाले एक्टर थलपति विजय इन दिनों में चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं. वो अपनी पार्टी टीवीके के उम्मीदावों के लिए वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं.

विजय जब भी किसी रोड शो या जनसभा में नजर आते हैं तो हजारों प्रशंसकों की भीड़ उन्हें घेर लेती है. उनकी जबरदस्त लोकप्रियता यह संकेत देती है कि सिनेमा से राजनीति में उनका कदम मजबूत समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे तमिलनाडु की राजनीति का एक जटिल और अनदेखा पहलू छिपा है. यह है जाति की भूमिका. खास बात यह है कि विजय के मामले में उनकी 'जाति-निरपेक्ष' पहचान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं. दरअसल तमिलनाडु को अक्सर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. यहां सामाजिक न्याय और समानता की बातें प्रमुख हैं. इसके बावजूद, राजनीति में जाति का प्रभाव गहराई से मौजूद है.

कर्नाटक में मचेगा घमासान... 4 मई होगी अहम

बेंगलुरु. कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर खींचतान आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है. 4 मई को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद राज्य की सियासत में हलचल बढ़ने के संकेत हैं.

हालांकि, इन चुनावों का कर्नाटक सरकार की स्थिरता पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन पर इनका प्रभाव पड़ सकता है. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा एक बार फिर चर्चा में है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि चुनाव नतीजों के बाद शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दोबारा मजबूत करने का यह अहम मौका हो सकता है, क्योंकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब करीब दो साल ही बचे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धारमैया खेमे ने कैबिनेट फेरबदल की मांग तेज कर दी है. इसे राजनीतिक पर्यवेक्षक प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने और 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले संदेश को रीसेट करने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं. बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया समर्थक करीब 30 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं. दूसरी ओर, शिवकुमार समर्थक भी चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, जहां वे नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर पार्टी आलाकमान पर दबाव बना सकते हैं.

दोनों नेताओं का मजबूत आधार

आने वाला महीना कर्नाटक कांग्रेस के लिए अहम साबित होने वाला है. सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार दोनों के अपने-अपने मजबूत सामाजिक और राजनीतिक आधार हैं. जहां सिद्दारमैया अहिंदा वर्गों में प्रभाव रखते हैं, वहीं शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय और संगठनात्मक ढांचे में मजबूत पकड़ रखते हैं. अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान इन प्रतिस्पर्धी दावेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाता है. फिलहाल उसकी रणनीति वेट एंड वॉच की बनी हुई है.

विशेष — दीदी को घेरने वाला चक्रव्यूह फार्मूला ओर चुनावी रणनीति

बंगाल में भाजपा कैसे बनी मजबूत ताकत?

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले एक दशक में एक ऐसे बड़े बदलाव की गवाह बनी है जिसने पुराने सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है.

कभी वामपंथी दलों और क्षेत्रीय राजनीति का अभेद्य किला माना जाने वाला यह राज्य अब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले का मैदान बन चुका है. यह बदलाव कोई रातों-रात नहीं आया बल्कि इसके पीछे वर्षों की योजनाबद्ध तैयारी और जमीन पर की गई कड़ी मेहनत छिपी है.

साल 2011 में जो पार्टी बंगाल के चुनावी नक्शे पर लगभग अदृश्य थी, वह आज राज्य की सत्ता की मुख्य दावेदार बनकर उभरी है. भाजपा की इस बढ़त ने न केवल तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं बल्कि बंगाल के पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को भी पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. इन सबके पीछे भाजपा ने कई रणनीतियों पर काम किया. बंगाल में भाजपा के विकास की कहानी को आंकड़ों के जरिए समझना बेहद जरूरी है.

साल 2011 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को महज तीन से चार प्रतिशत वोट मिले थे और उसकी झोली में एक भी सीट नहीं आई थी. इसके पांच साल बाद 2016 में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर दस प्रतिशत हुआ और विधानसभा में पहली बार उसके तीन प्रतिनिधियों ने प्रवेश किया. असली चमत्कार 2021 के चुनावों में हुआ जब भाजपा ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाते हुए 38 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया और 77 सीटों पर कब्जा जमाया. महज दस साल के भीतर तीस प्रतिशत से ज्यादा का यह वोट स्विंग भारत के किसी भी राज्य में सबसे तेज राजनीतिक उभारों में से एक माना जाता है.

> भाजपा ने बंगाल को एक लक्षित राज्य के रूप में चुनकर अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू किया था. इसकी शुरुआत साल 2014 के लोकसभा चुनावों से हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार पार्टी ने बंगाल में अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराई. इसके बाद 2019 का चुनाव पार्टी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उसने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया और उसका वोट शेयर करीब चालीस प्रतिशत तक पहुंच गया. इस बड़ी जीत से यह साफ संदेश गया कि भाजपा अब ममता बनर्जी की सरकार को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार है. पार्टी ने इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज जैसे मुद्दों को आक्रामक ढंग से उठाकर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई.